

न्यायालय:- पंकज कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१ बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)

व्यवहार वाद क्रमांक-59 ए/2017

संस्थित दिनांक-15/03/2017

फाईलिंग नंबर 265/2017

नागोराव पिता स्व. उमराव डोंगरे उम्र 72 वर्ष,
निवासी ग्राम दभेरी तहसील जिला बैतूल म.प्र.,
हाल मु. भगतसिंह वार्ड सदर बैतूल
तह. जिला- बैतूल (म0प्र0)

.....वादी

विरुद्ध

- 1{एक}.रमेश पिता स्व. उमराव डोंगरे उम्र 60 वर्ष,
जाति मेहरा नि. ग्राम सेलगांव तह. जिला बैतूल।
- 2{दो} म.प्र.शासन,
द्वारा-श्रीमान कलेक्टर बैतूल म.प्र.
3. इमरती बाई जौजे मुन्नीलाल झरबडे उम्र 56 वर्ष,
नि. भयावाड़ी (पांगरा) पुलिस चौकी खेडीसांवलीगढ,
तह. जिला बैतूल
4. कमलतीबाई जौजे मारोती निरापुरे उम्र 50 वर्ष,
जाति मेहरा नि. ग्राम जम्बाडा तह. मुलताई
जिला बैतूल
हाल-हवाई अड्डा के पास पाथाखेडा तह.
घोडाडोंगरी जिला बैतूल

.....प्रतिवादीगण

!! आदेश !!

(आज दिनांक 11/10/2017 को पारित)

- (1) इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र
अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यप्रसं का निराकरण

P.T.O.

किया जा रहा है।

(2) प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में भाई-बहन हैं उनके पिता स्व. उमराव थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि उनके पिता उमराव की थी।

(3) संक्षेप में वादपत्र अभिवचन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई-बहन हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व. उमराव थे जिनकी ग्राम बावई में भूमियां स्थित थी। उनके पिता की भूमियों का दिनांक 15-10-1993 में तहसीलदार के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण तथा इनकी मां जसोदाबाई के मध्य आपसी सहमति के आधार पर भूमियों का विभाजन हुआ था जिसके आधार पर बहन इमरती व कमलती द्वारा कोई भूमि नहीं लेना व्यक्त किया था और उन्होंने अपना हिस्सा स्वेच्छया से त्याग दिया था। उक्त बंटवारे में वादी को खसरा नंबर 177/3 रकबा 0.506, खसरा नंबर 174/2 रकबा 0.203 एवं खसरा नंबर 176 रकबा 0.091 हे. भूमियां तथा प्रतिवादी क्र. 1 को खसरा नंबर 177/2 रकबा 0.506, खसरा नंबर 174/1 रकबा 0.202, खसरा नंबर 173/3 रकबा 0.091 हे. मौजा बावई की भूमियां बंटवारे में मिली थी। वादी तथा प्रतिवादी क्र. 1 को प्राप्त भूमियों में मां जसोदाबाई का नाम, मात्र उसके जीवनकाल तक के लिये रखा गया था। जसोदाबाई की मृत्यु दिनांक 11-08-2012 को हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 बंटवारे में मिली भूमियों में शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे थे। प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा उसके हिस्से में आपसी सहमति से आई भूमियां खसरा नंबर 174/1 रकबा 0.202, 176/3 रकबा 0.091, खसरा नंबर 177/2 रकबा 0.101 हे. कुल रकबा 0.394 हे. भूमियां यादोराव वल्द बाबूराव निवासी दभेरी वाले को विक्रय कर दी है। वादी द्वारा जसोदाबाई की मृत्यु उपरांत राजस्व अभिलेख में उसके साथ खसरा नंबर 177/3, 174/2 एवं 176/1 से नाम काटे जाने बाबत एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार बैतूल के समक्ष पेश किया था। नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 6अ-06 वर्ष 2012-13 पारित आदेश दिनांक 30-06-2014 अनुसार जसोदाबाई का नाम वादी के साथ जो राजस्व अभिलेख में दर्ज था, को निरस्त किया गया परंतु प्रतिवादीगण का नाम विधि विरुद्ध तरीके से जोड़े

जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये जिनकी अपील उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को की गई थी जो निरस्त कर दी गई है। प्रतिवादीगण द्वारा उनके हिस्से में प्राप्त भूमि विक्रय कर दी गई है। वादग्रस्त भूमि जो वादी के नाम पर दर्ज है, उसमें प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में निरस्त किये जाने एवं वादग्रस्त भूमि पर एक मात्र भूमि स्वामी वादी है, की घोषणा हेतु दावा पेश करते हुये इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है कि प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा नायब तहसीलदार बैतूल के न्यायालय में एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109, 110 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें नियत तारीख 16-03-2017 है, अतः वह कार्यवाही प्रकरण के निराकरण तक स्थगित रखी जावे। आवेदन पत्र के समर्थन में वादी की ओर से स्वयं तथा देवानंद नागले, तुलाराम, शिवचरण, शिवराम, चंद्रकलाबाई, श्रीराम महजान के शपथ पत्र पेश किये हैं जिन्होंने वादी के शपथ पत्र के अभिवचनों का ही समर्थन किया है।

(4) प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 मध्यप्रदेश शासन औपचारिक पक्षकार है, उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

(5) प्रतिवादी क्र. 4 द्वारा जवाबदावा पेश कर संपूर्ण वादपत्र के अभिवचनों को स्वीकार किया है।

(6) प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा जवाबदावा पेश कर स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रतिकूल अभिवचनों को अस्वीकार किया गया है तथा अभिकथित किया गया है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद वादी नागोराव ने बंटवारा कराने की इच्छा जाहिर की थी तो पिता के नाम दर्ज भूमियों का बंटवारा किया गया था। बंटवारा की सारी कार्यवाही वादी ने ही की थी। मां जसोदाबाई का नाम, दोनों पुत्रियों का नाम भूमियों पर 1/2, 1/2 हक बंटवारे के समय से ही रहा है जिसका उल्लेख राजस्व अभिलेखों में रहा है। वादग्रस्त भूमि में बहनों का भी हिस्सा है। मां का नाम केवल जीवनकाल तक के लिये नहीं रखा गया था, उक्त भूमियों में उनकी मां का भी हिस्सा था। वादी ने मां जसोदाबाई की मृत्यु के पश्चात नाम काटे जाने का आवेदन पेश किया था जिसके साथ नाम काटा जाकर उनके विधिक

वारसानों का नाम नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज किया गया है जो विधि अनुकूल है जिसकी अपील वादी द्वारा की गई थी जो आधारहीन होने से निरस्त कर दी गई है और जसोदाबाई के वारसानों का नाम यथावत् रखा गया।

(7) वादी वन विभाग में शासकीय सेवा में है तथा वह कई वर्षों से मां से पृथक् रहता है। मां जसोदाबाई का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था जिसके इलाज में रूपयों की आवश्यकता थी, वादी ने प्रतिवादी क्र. 1 की माता के इलाज हेतु आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया था, तब प्रतिवादी क्र. 1 तथा मां जसोदाबाई के इलाज के खर्च हेतु उसे जमीन बेचना पड़ा था। वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी क्र. 1 का भी हिस्सा है और वे 1/4, 1/4 अंश प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा दावा एवं आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है तथा यह भी अभिकथित किया है कि राजस्व न्यायालय द्वारा नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में स्वयं का एवं इमरतीबाई और रमेश के शपथ पत्र पेश किये हैं जिन्होंने अभिकथित किया है कि वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी क्र. 1 का भी हक व हिस्सा है।

(8) अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र के निराकरण के लिये तीन बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होता है :-

1- क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है ?

2- क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?

3-क्या अपूर्ण क्षति का बिंदु आवेदक के पक्ष में है ?

(9) उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर विचार सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।

(10) वादीगण द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि जो वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज थी, वह उनके पिता उमराव की थी, उनकी मृत्यु के बाद आपसी सहमति के

आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा दिनांक 15-10-1993 को विभाजन हुआ था जिसमें बहनों ने स्वेच्छया से अपना हक त्याग दिया था तथा वादी को खसरा नंबर 177/3 रकबा 0.506, खसरा नंबर 174/2 रकबा 0.203 एवं खसरा नंबर 176 रकबा 0.091 हे. भूमियां तथा प्रतिवादी क्र. 1 को खसरा नंबर 177/2 रकबा 0.506, खसरा नंबर 174/1 रकबा 0.202, खसरा नंबर 173/3 रकबा 0.091 हे. भूमियां प्राप्त हुई थी। वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 की भूमियों पर मां का नाम, मात्र उनके जीवनकाल तक के लिये दर्ज किया गया था लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जब वादी ने उसके और उसकी मां जसोदाबाई के नाम दर्ज भूमि पर मां का नाम निरस्त करने का आवेदन दिया, तब राजस्व न्यायालय द्वारा मां का नाम तो निरस्त किया था लेकिन साथ ही प्रतिवादीगण का नाम भी विधिक वारसान के रूप में दर्ज किया गया जबकि इन भूमियों पर प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी ने उसकी भूमियां जो मां के साथ उसके नाम दर्ज थी, उसको विक्रय कर दी है और अब वादग्रस्त भूमियां जो वादी के नाम पर है, उसमें भी हक हिस्सा चाह रहा है जबकि प्रतिवादी ने अभिकथित किया है कि वादी के नाम पर जो भूमियां थी, उसमें मां का भी हिस्सा था और उसकी मृत्यु के बाद सभी बहनों और प्रतिवादी क्र. 1 का विधिक वारसान के रूप में राजस्व न्यायालय द्वारा विधि अनुसार नाम दर्ज किया गया है। बहनों ने अपना कोई हक वगैरह नहीं त्यागा है उनका भी हिस्सा है।

(11) वादी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के माध्यम से इस आशय का स्थगन चाहा गया है कि प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा नायब तहसीलदार बैतूल के न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 109, 110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत पेश किया गया है जिसका भी स्थगन चाहा है। प्रतिवादी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो चुका है तथा कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है। उभय पक्ष की ओर से वादग्रस्त भूमियों से संबंधित जो राजस्व अभिलेख पेश किये गये हैं, उसके अनुसार वादग्रस्त भूमियों पर वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है तथा प्रतिवादीगण की ओर से राजस्व न्यायालय का दिनांक 24-05-2017 का आदेश भी पेश किया गया

है जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमियों में सभी सह-स्वामियों का नाम पृथक-पृथक विभाजन कर बंटवारा अनुसार दर्ज किया जा चुका है। चूंकि राजस्व कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और अब उसके स्थगन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है और इस प्रकार आवेदन पत्र वर्तमान स्थिति में औचित्यहीन रह गया है।

(12) वादी द्वारा वादग्रस्त भूमियों में स्वत्व की घोषणा हेतु दावा पेश किया है, राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज है, उभय पक्ष द्वारा दावा भी स्वीकृत है। ऐसी दशा में वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया तो प्रकरण पाया जाता है लेकिन जहाँ तक अपूर्ण क्षति और सुविधा के संतुलन की बात है, चूंकि राजस्व कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, बंटवारा किया जा चुका है, राजस्व अभिलेखों में उभय पक्ष का नाम पृथक-पृथक दर्ज हो चुका है। ऐसी दशा में राजस्व न्यायालय की कार्यवाही स्थगित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः वादी को इस संबंध में कोई अपूर्ण क्षति होने का भी प्रश्न नहीं है, अतः वादी की ओर से पेश आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर	मेरे निर्देश में टंकित
हस्ताक्षरित किया गया ।	किया गया ।

(पंकज कुमार)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१
बैतूल

(पंकज कुमार)

बैतूल